Central Issue Prices for different varieties of rice have been as follows:-

(Rs. per quintal)

Variety of rice	Central Issue Prices
Common	537
Fine	617
Super Fine	648

Rice meant for distribution in Revamped PDS area is being issued to all State Governments at specially subsidised prices which are Rs. 50/- per quintal lower than the Central issue Prices for the PDS areas.

Government of Karnataka has reported that rice is being sold at Rs. 3.20 per kg. under the PDS for the rural poor and urban slum dwellers in Karnataka. Government of Karnataka has reported that under this scheme which has been in operation from 1.4.95, all the rural poor whose annual income is below Rs. 6400/- per annum and urban slum dwellers are covered. Around 52 lakh families in Karnataka are covered under the Scheme.

Karnataka Government has reported that the State Government is providing a subsidy of Rs. 367.65 per quintal under this scheme.

बिजली के उत्पादन के संबंध में योजना का सर्वेक्षण

*303. **श्री रामजीलाल:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना के मध्य में इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण करवाया है कि बिजली क्षेत्र में निवेशित पूंजी के अनुपात में बिजली का उत्पादन होता है;

(ख) क्या योजना आयोग, इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और धनराशि आवंटित करेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हरियाणा के बारे में ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) विद्युत सृजन तथा विद्युत क्षमता वृद्धि विद्युत क्षेत्रक में समग्र पूंजी निवेश की मात्रा से सम्बन्धित है। बहरहाल, विद्युत सृजन संयंत्र उपलब्धता, संयंत्र लोड फेक्टर तथा नई क्षमता वृद्धियों जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

(ख) केन्द्र तथा राज्य योजनाओं, दोनों में विद्युत क्षेत्रक के लिए परिव्यय, विशिष्ट परियोजनाओं हेतु अपेक्षाओं, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधनों, समग्र संसाधन दबावों के अन्दर उपलब्ध करायी जा सकने वाली बजटीय सहायता तथा केन्द्रीय व राज्य योजनाओं में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किये जाते हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों के लिए आठवीं योजना के पहले चार वर्षों (1992-93 से 1995-96) के दौरान विद्युत क्षेत्रक के लिए अनुमोदित परिव्यय सातवीं योजना के विद्युत क्षेत्रक के कुल 79589 करोड़ रुपये के परिव्यय का 87.27 प्रतिशत है।

(ग) हरियाणा राज्य के लिए आठवीं योजना के पहले चार वर्षों के वास्ते विद्युत क्षेत्रक हेतु कुल अनुमोदित परिव्यय 933.63 करोड़ रुपये हैं, जो आठवीं योजना के विद्युत क्षेत्रक के 1702 करोड़ रुपये के परिव्यय का 54.85 प्रतिशत है।

Tea producing Districts in the Country

*304. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the names of tea gardens in Assam owned by Government and the area under tea plantation, garden-wise;

(b) the details of tea research/experimental centres affiliated to Government and the amount spent thereon during the last three years, year-wise break-up;

(c) the names of top ten tea producing districts in the country with tea produced during the above period, district-wise and year-wise;

(d) the details of total quantum of tea auctioned in the tea auction centres in the country during the above period, centre-wise and year-wise; and